नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया.

“आज प्रधान कार्यालय में वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया. नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ हर्ष कुमार भनवाला ने श्री एच आर दवे, उप प्रबंध निदेशक के साथ प्रेस के 30 से अधिक प्रमुख पत्रकारों को संबोधित किया. नाबार्ड ने पिछले वर्ष बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और नाबार्ड का तुलन-पत्र पिछले वर्ष के रु.3,10,385 करोड़ से 12.16% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2017 को रु.3,48,119 करोड़ हो गया है.”

"वर्ष 2016-17 के दौरान हमने ऋण की प्रमात्रा और पहुंच को बढ़ाने, लास्ट माइल डिजिटाइजेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्राथमिकता दी." - डॉ भनवाला, अध्यक्ष, नाबार्ड

ग्रामीण पर्यावरण में नाबार्ड

नाबार्ड भारत की शीर्ष विकास वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1982 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई. अपने शुरुआती वर्षों में शुद्ध रूप से पुनर्वित्त उपलब्ध कराने की भूमिका निभाने वाला नाबार्ड आज ग्रामीण भारत के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी विकास वित्तीय संस्था है. नाबार्ड ने ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ बनाने के अलावा अनेक क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का

विकास, वित्तीय समावेशन के दायरे को बढ़ाना, महिला सशक्तीकरण, पूंजी निर्माण और कृषि को जलवायु परिवर्तन रोधी बनाना.

ऋण और ऋणेतर आयोजना की प्रक्रिया में बैंकिंग उद्योग और अन्य हितधारकों को सहयोग देने वाली अपनी जिला और राज्य स्तरीय आयोजना के माध्यम से वर्ष 2016-17 में नाबार्ड ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वैचारिक दिशा देने वाली संस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है.

हम अब वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपने योगदान का एक संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं. इसके अलावा हम निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न कर रहे हैं.

क. हमारा पुरस्कृत कारपोरेट ब्रोशर - 'आंकड़ों से परे'.
ख. "सिम्प्ली डेवलपमेंट" - देश में जमीनी स्तर पर हमारे कुछ सर्वोत्कृष्ट प्रयासों की जानकारी
ग. वर्ष के दौरान जारी प्रेस विज्ञप्तियों की प्रमुख बातें.

आंकड़ों में नाबार्ड - 2016-17

(रु. करोड़ में)

विवरण	**31.3.2015**	**31.3.2016**	**31.3.2017 (अ-लेखापरीक्षित)**	**वार्षिक वृद्धि (%)**
तुलन-पत्र का आकार	2,85,809	3,10,385	3,48,119	12.16
पूंजी और आरक्षित निधियां	24,601	27,426	31,414	14.54
बकाया ऋण और अग्रिम	2,52,369	2,65,448	3,08,625	16.27
उनमें से				
दीर्घावधि ऋण	68,458	89,943	1,06,327	18.22
आरआईडीएफ के तहत ऋण	83,545	91,384	1,00,982	10.50
कर-पश्चात् लाभ	2,403	2,524	2,631	4.24
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	37.39	38.60	46.00	19.17

व्यवसाय

i. वर्ष 2016-17 के दौरान नाबार्ड का बकाया पुनर्वित्त रु.1,41,267 करोड़ के अब तक के सबसे उंचे स्तर पर पहुंचा (2015-16 में रु.1,19,770 करोड़ - वृद्धि 18%) ऐसा अब तक के सर्वाधिक संवितरण रु. 53,504 करोड़ (पिछले वर्ष से 11% अधिक) के कारण हासिल हुआ.

ii. नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रु.83,355 करोड़ का संवितरण कर 2016-17 के दौरान कृषक वर्ग की अल्पावधि ऋण जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके अलावा नाबार्ड ने कृषि, अनुषंगी और बुनकर क्षेत्रों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पावधि (अन्य) और अल्पावधि (बुनकर) के अंतर्गत रु.1,510 करोड़ संवितरित किए.

iii. विमुद्रीकरण के बाद उठाए गए कदम

- ✓ किसानों की ऋण तक पहुंच को अधिक सुगम बनाने के लिए सहकारी बैंकों और समितियों को रु.20,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई. इस अतिरिक्त मंजूरी में से रु.17,774 करोड़ की राशि सहकारी बैंकों को संवितरित की जा चुकी है. इस कदम से 2016-17 के दौरान रबी की फसल के लिए रियायती दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई.
- ✓ विमुद्रीकरण के कारण किसानों को हुई नकदी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए 2016 के खरीफ मौसम में सहकारी बैंकों द्वारा मंजूर और संवितरित अल्पावधि फसल ऋण पर दो महीने (नवंबर-दिसंबर 2016) के ब्याज की माफी की गई. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 15407473 किसानों के खातों में रु.458.28 करोड़ की राशि जमा की गई.

iv. दीर्घावधि ऋण के लिए पुनर्वित्त, जो दीर्घावधि पूंजी निर्माण का सुस्थापित संकेतक है, रु.53,504 करोड़ की नई उंचाई पर पहुंच गया. यह उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्षों में यह 35% वार्षिक की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है.

v. **ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ)** के अंतर्गत संवितरण पिछले वर्ष के रु.23,507 करोड़ की तुलना में 8.8% बढ़कर रु. 25,600 करोड़ हो गया. 31 मार्च 2017 को आरआईडीएफ़ की 22 खेपों में कुल संचयी मंजूरी रु.2,87,129 पहुंच गई जिसके समक्ष रु.2,29,809 करोड़ संवितरित किए गए.

भारत के ग्रामीण बुनियादी ढांचे में नाबार्ड का योगदान

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित उल्लेखनीय उपलब्धियों के रूप में आरआईडीएफ के माध्यम से किए गए नाबार्ड के प्रयासों के परिणाम संक्षेप में देखे जा सकते हैं:

- 291.00 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण.
- 4.28 लाख कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण.
- 10.37 लाख मी. लंबाई के ग्रामीण पुलों का निर्माण.
- आय के स्तर, कृषि उत्पादन और जीवन स्तर की गुणवत्ता पर एक स्पष्ट और सत्यापित सकारात्मक प्रभाव.

vi. सिंचाई के क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने वाली दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के अंतर्गत नाबार्ड ने कुल रु.49,890 करोड़ के ऋणों के साथ केंद्र सरकार के हिस्से के समक्ष 81

परियोजनाओं और राज्य सरकारों के हिस्से के समक्ष 63 परियोजनाओं को मंजूरी दी. इस निधि के अंतर्गत रु.9,086 करोड़ की राशि पहले ही संवितरित की जा चुकी है.

vii. पिछले वर्ष नाबार्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों, फेडरेशनों और सहकारी संस्थाओं को सीधे वित्तपोषण के क्षेत्र में सघन प्रयास किए हैं. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के अंत में 55% की वृद्धि दर्ज करते हुए इस प्रकार के ऋणों का संवितरण रु.21,386 करोड़ तक पहुंच गया. राष्ट्र निर्माण के अधिदेश के अनुरूप नाबार्ड ने वित्तपोषण के इस क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई, शीत भंडारण, सड़कों और पवन परियोजनाओं पर निरंतर ध्यान दिया है.

viii. भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि (डब्ल्यूआईएफ) के अंतर्गत संवितरण पिछले वर्ष के रु.1,046 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान बढ़कर रु.1,150 करोड़ हो गया. संचयी संवितरण: रु.3,400 करोड़.

ix. वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि ऋण प्रवाह के रु.9.00 लाख करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रु.9.60 लाख करोड़ का ऋण प्रवाह हुआ (आंकड़े अनंतिम). (सावधि ऋण - रु.3,37,140 करोड़; फसल ऋण - रु.6,22,685 करोड़.)

विकास कार्य

i. वित्तीय समावेशन और नाबार्ड

वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय दृष्टि से समावेशनमूलक नकदी-रहित अर्थव्यवस्था के निर्माण के उद्देश्य से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डिजिटाइज़ करने की दिशा में कुछ अत्यंत उत्साहपूर्ण प्रयास किए.

- वर्ष के दौरान नाबार्ड ने 82,000 से अधिक गांवों के लिए 2.05 लाख पीओएस उपकरणों के लिए सहायता मंजूर की. लक्ष्य है प्रति गांव दो पीओएस उपकरणों के माध्यम से 1 लाख गांवों तक पहुंचना. नाबार्ड ने ईएमवी चिप-आधारित रुपे किसान कार्डों की खरीद के लिए भी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता दी.
- नाबार्ड के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1 करोड़ रुपे किसान कार्ड जारी करने में सफल हुए हैं. दरअसल केवल राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक को छोड़कर सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 100% लाइव/ पात्र केसीसी को शामिल कर लिया है.
- नाबार्ड ने इस दिशा में सहकारी बैंकों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है. आज सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए कुल रुपे केसीसी की संख्या 52.38 लाख है. नाबार्ड ने उल्लेखनीय रूप से कम समय में 380 लाइसेन्सी सहकारी बैंकों में से 190 को कार्ड टेक्नोलोजी पर आने में समर्थ बनाया है. इससे अल्प समय में ही ग्रामीण बैंकिंग पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा.

- विमुद्रीकरण के बाद नाबार्ड ने तेजी से कदम उठाते हुए डिजिटल वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए ताकि विविध डिजिटल बैंकिंग प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए और उनके इस्तेमाल की व्यावहारिक जानकारी दी जाए. ये कार्यक्रम स्कूलों में भी करवाए जा रहे हैं.
- नाबार्ड सौर ऊर्जा को वित्तीय समावेशन की दृष्टि से एक नया रास्ता दिखाने वाली प्रौद्योगिकी मानता है. सेवा उप-क्षेत्रों में बिजली की कमी और कनेक्टिविटी के अभाव की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से नाबार्ड कियोस्क/ फिक्स्ड सीएसपी के लिए सौर ऊर्जा से संचालित वी-सैट स्थापित करने के लिए सहायता देता है. नाबार्ड ने वर्ष 2016-17 में रु. 274.78 करोड़ मंजूर किए जिसके साथ 8257 सेवा उप-क्षेत्रों में ऐसे वी-सैट स्थापित करने के लिए संचयी मंजूरी रु.308.46 करोड़ पहुंच गई.
- **लकी ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना:** नीति आयोग द्वारा डिजाइन की गई 'लकी ग्राहक योजना' और 'डिजि-धन व्यापार योजना' ग्राहकों और व्यापारियों के स्तर पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई हैं. इन योजनाओं के लिए वित्तीय समावेशन निधि से धन उपलब्ध कराया जा रहा है. एनपीसीआई नकद पुरस्कारों (दैनिक, साप्ताहिक और मेगा पुरस्कार) के लिए डिजिटल लेन-देन आईडी में से इलेक्ट्रोनिक ड्रॉ के जरिए विजेता तय करता है. योजनाएं 25 दिसंबर 2016 को शुरू हुईं और 14 अप्रैल 2017 को मेगा ड्रॉ होने तक दैनिक और साप्ताहिक आधार पर चलेंगी. यजनाओं पर होने वाला रु. 340 करोड़ का खर्च वित्तीय समावेशन निधि से किया जा रहा है. 31 मार्च 2017 तक योजनाओं के अंतर्गत रु.275 करोड़ का खर्च हुआ है.

ii. **नाबार्ड अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वे**

नाबार्ड ने 2016-17 में नाबार्ड अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वे का काम शुरू किया जिसका लक्ष्य परिवार के स्तर पर आजीविका और वित्तीय समावेशन के विविध पहलुओं की बेहतर समझ हासिल करना है. सर्वे में 40,000 परिवारों को शामिल किया जाएगा और उम्मीद है कि इससे ग्रामीण वित्तीय समावेशन के बारे समझ के वर्तमान स्तर में जो महत्त्वपूर्ण अंतराल है वह दूर होगा. अब तक नमूना परिवारों के 50% को कवर किया जा चुका है और अंतिम रिपोर्ट 2017-18 में मिलनी है.

iii. **ई-शक्ति - स्वयं सहायता समूह आंदोलन का भविष्य:** स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए **ई-शक्ति परियोजना** को दूसरे चरण में 22 और जिलों में शुरू किया गया. इस तरह परियोजना के कार्यान्वयन वाले जिलों की संख्या 24 हो गई. अब तक 18,515 गांवों के 1.28 लाख समूह डिजिटाइज़ किए जा चुके हैं जिन्होंने 14.70 लाख परिवारों को स्पर्श किया है. पूरे देश में अब 92 फील्ड-स्तरीय कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां परियोजना से जुड़ी हैं.

iv. **स्वयं सहायता समूह आंदोलन का विकास**

क्र. सं.	विवरण	2016-17 में संख्या (लाख)	संचयी संख्या 31.03.2017 (लाख)	2016-17 में राशि (करोड़)	संचयी राशि 31.03.2017 (करोड़)
1	बचत-सहबद्ध समूह	6.54	85.56	479	14,170
2	ऋण-सहबद्ध समूह	13.19	46.73	20,370	57,119
3	संयुक्त देयता समूह	5.13	22.22	5,545	22,882

v. हाल ही में शुरू किए गए एलईडीपी (आजीविका उद्यम विकास कार्यक्रम) के अंतर्गत कृषि और कृषीतर दोनों क्षेत्रों की गतिविधियों की 100 परियोजनाओं के अंतर्गत रु.422.21 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई ताकि स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं, स्थायी आजीविका सृजित की जा सके.

vi. जलवायु को सहने में सक्षम खेती

- ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में 166.297 मिलियन यूएस डॉलर के परियोजना परिव्यय से भूमिगत जल के पुनर्भरण और सौर सूक्ष्म सिंचाई के नाबार्ड ने ग्रीन क्लाइमेट फंड को एक नई तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे मंजूर किया गया. यह इस दिशा में आश्वस्त करने वाली शुरुआत है.
- अनुकूलन निधि के तहत नाबार्ड ने वर्ष 2016-17 में 2.55 मिलियन यूएस डॉलर का कुल अनुदान मंजूर किया. अब तक छह परियोजनाओं के लिए संचयी रूप से 9.85 मिलियन यूएस डॉलर का संवितरण किया जा चुका है.
- नाबार्ड ने वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन निधि से 07 परियोजनाओं के लिए रु. 154.55 करोड़ मंजूर किए. संचयी संवितरण रु. 396.85 करोड़ रहा जिसमें से रु. 44.87 करोड़ जारी किए गए हैं.
- नाबार्ड ने वर्ष 2016-17 में जल संरक्षण और जल उपयोग दक्षता पर 38,000 गांवों में जल अभियान का संचालन किया.

संस्था विकास और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में नाबार्ड की भूमिका

- नाबार्ड की अनुशंसा के आधार पर 23 गैर-लाइसेन्सी बैंकों में से 18 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेन्स जारी किया गया.
- अपनी पर्यवेक्षकीय भूमिका के तहत नाबार्ड ने वर्ष के दौरान 314 बैंकों (33 रास बैंक, 56 क्षेग्रा बैंक, 213 जिमस बैंक, 10 रासग्रावि बैंक और 2 शीर्ष स्तरीय समितियां) का निरीक्षण किया.